

इसको उठा रहे हैं... (अवधान) ।
कालिंग एटेंशन, श्री भाभड़ा ।

श्री रामेश्वर सिंह : यह अंग्रेजी
का नवाज नहीं है... (अवधान) ।

SHRI PILOO MODY: The official
language of Nagaland is English.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He does
not know. What can I do?

SHRI MANUBHAI PATEL (Gujarat): It should be bilingual. The official policy of the Government should be followed.

श्री उपसभापति : ठीक है, बाइलिङ्गल
हो ।

श्री जी० सी० मट्टाचार्य (उत्तर
प्रदेश) : अब स्पेशल मेंशन खोजिये ।

श्री उपसभापति : स्पेशल मेंशन
कालिंग मोशन को लेते के बाद होते हैं ।

श्री जी० सी० मट्टाचार्य : पहले भी
होते हैं ।

श्री उपसभापति : आप तो इस
सदन में कई वर्षों से हैं । कालिंग
एटेंशन मोशन के बाद स्पेशल मेंशन
होते हैं ।

श्री जी० सी० मट्टाचार्य : बहुत बार
स्पेशल मेंशन पहले भी होते हैं ।

श्री उपसभापति : कभी नहीं होते
हैं ।

श्री जी० सी० मट्टाचार्य : कई बार
होते हैं ।

श्री उपसभापति : आपसे बहुत क्या
करेंगे आप वो सुनते ही नहीं हैं ।
श्री भाभड़ा ।

CALLING ATTENTION TO A MAT- TER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Laboratory findings that the
wheat imported from Australia was
mixed with a deadly insecticide
fenitrothion

श्री हरी शंकर भाभड़ा (गजस्थान) :
श्रीमान्, मैं प्रयोगशाला के इन निष्कर्षों के
समाचार कि आस्ट्रेलिया से आयातित गेहूँ
में एक घातक कीटनाशी फेनाइट्रोथियोन
मिला हुआ था तथा इस संबंध में सरकार
द्वारा की गई कार्यवाही की ओर कृषि तथा
ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्री का
ध्यान दिखाना है ।

THE MINISTER OF AGRICUL-
TURE AND RURAL DEVELOPMENT
AND CIVIL SUPPLIES (RAO
BIRENDRA SINGH): Mr. Deputy
Chairman, Sir, . . . attention of the
Government has been drawn to a
report under the heading "Deadly
Wheat from Australia" appearing in
the Statesman of the 2nd March,
1982.

In order to counter any unnecessary
apprehension that the report may
cause, the factual position was issued
to the press the same day.

Briefly, the position is that varieties
of grain-protectants are used by differ-
ent countries depending on their effec-
tiveness against the insect strain pre-
valent in those countries. Australia
is accustomed to the use of Fenitro-
thion for the purpose of protecting
grain in storage. The tolerance limit
of the residue of this protectant as
prescribed by the World Health Or-
ganization and the Food and Agricul-
ture Organisation Codex is 10 parts
per million. The wheat currently
being imported from Australia is ana-
lysed for the residue of the grain-
protectant as per the normal proce-
dure both at the time of loading and
on arrival at Indian ports. While the
residue level is not exceeding seven

parts per million at the time of loading, it is only between one and three parts per million on arrival and even this wears off during normal storage. The residue level at the time of receipt minimise the need for a repeat dosage of grain-protectant normally used in the course of storage within the country. By the time the wheat is issued for consumption, the residue level will come down further to well within limits prescribed by the rules framed under the Prevention of Adulteration Act.

In the circumstances!, it is wrong and even mischievous to suggest, as the report does, that the wheat cannot be used or that it will be necessary for Government to find other ways of replenishing this quantity.

श्री हरी शंकर मामड़ा : मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय ने लगभग वही बात अक्षरशः पढ़ दी है जो आज के अखबारों में उनके मंत्रालय द्वारा दी गई है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं कहां से लाऊंगा ?

श्री हरी शंकर मामड़ा : आपने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय अपने बुद्धि का भी प्रयोग करें और केवल सरकारी अधिकाधिकारों के आधार पर या उनके विश्वास पर सरकार को चलाने में थोड़ा सा पुनर्विचार करें। इसी सौदे में आपके यहां से श्री बी० एस० राघवन, एडीशनल सेक्रेटरी और श्री एस० बी० शास्त्री, फाइनैसियल एडवाइजर बड़े गुप्त रूप से छुट्टी लेकर आस्ट्रेलिया गये थे और इस सौदे को गुप्त रखा गया था। लेकिन आपकी सरकार इसकी इनफॉर्मिडेंट थी कि उसी समय इस बात का पता अमेरिका को चल गया और अमेरिका के ग्रैंडर सेक्रेटरी मि० लार्डविक आप

से स्वयं मिले थे। और उन्होंने यह आपको आफर दी कि हम आपको चाहें जितना गेहूं आप चाहें जितनी क्रेडिट पर मंगाना चाहते हैं, देने को तैयार हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपने यहां से जो कार्यवाही होती है वह इतनी विश्वसनीय नहीं है। गोपनीय रखने के बावजूद भी प्रकट हो जाती है। तो मान्यवर, यह जो अखबारों में इन गेहूं के अन्दर जो कीटनाशक दवाओं का प्रभाव छुपा है यह खबर बनाघट्टा खबर नहीं है। अगर किसी ने बनाई है तो आपके ही सरकारी विभागों ने कहीं न कहीं से। जनहित में इसको बताया है, इसके प्रचारित किया है। इसलिए मान्यवर, मंत्री महोदय, चले गये हैं और...

श्री उपसभापति : वह सुन रहे हैं।

श्री हरी शंकर मामड़ा : उनको सुनाना जरूरी है। वह आ जायेंगे तो मैं कहूंगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आपकी सुन रहा हूँ।

श्री हरी शंकर मामड़ा : लेकिन मुझे दिखाई यह नहीं दे रहा है। इस समय मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनको तो आप रोज सुनते हैं। मैं यह कहना चाहता था मंत्री महोदय कि यह जो खबर आई है और अब जो उन्होंने इसका जवाब दिया है, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी है और इसकी जांच मंत्री महोदय जनहित की दृष्टि से स्वयं करें। मुझे पता है मंत्री महोदय कि जब कभी भी उनके विभाग के किसी महत्वपूर्ण अधिकारी के खिलाफ पार्लियामेंट में प्रश्न उठाता है तो आपको उसे डिफेंड करना पड़ता है चाहे बाहर फिर उनके आप कान खींचते होंगे, जवाबतलब

[श्री हरी शंकर भागड़ा]

करते होंगे। लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर घर आकर उनको किसी न किसी तरह से आपको डिफेंड करना पड़ता है। परन्तु यह जो मामला है यह जन-हित से सम्बन्धित है, जनता के प्राणों से इसका संबंध है, इसलिये कृपया इस संबंध में आप व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानकारी करें कि यह खबर जो छपी है इस खबर में और जो आपने आज जवाब दिया है, इसमें कौन सी बात सही है। इसकी जानकारी आपको व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए, केवल सरकारी अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए।

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि आपने गेहूं इम्पोर्ट किया...

श्री उपसभापति : यह सवाल आप छोड़ बीजिये जो इसमें मिलाया गया है उस पर ही पूछिये...

श्री हरी शंकर भागड़ा : श्रीमन, विषय को इतना टू टेक्नीकल मत बनाइये।

श्री उपसभापति : आप जो...

श्री हरी शंकर भागड़ा : उपसभापति महोदय, आप मेरा समय ले रहे हैं।

श्री उपसभापति : जो मुख्य मुद्दा है उस पर बोलिये।

श्री हरी शंकर भागड़ा : मैं जो कुछ कह रहा हूँ वेत हित में कह रहा हूँ।

श्री उपसभापति : आप इम्पोर्ट की बात छोड़िये।.....(व्यवधान)

श्री मिश्र कृष्ण झा (बिहार) : आपने सुना नहीं और कह दिया कि रिलेबेन्ट नहीं है। यह बात उनको कहने बीजिये...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप बैठिये। जो मुख्य प्रश्न उठा है सरकार ने उससे इंकार कर दिया। जो प्रश्न है उस पर पूछिये। बिना वजह इधर उधर की बात कह कर...(व्यवधान)....

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उसके अनौचित्य को बता रहे हैं, इसको सुनिये...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : इसको छोड़िये.. (व्यवधान).. कृपा करके बैठ जाइये।

श्री हरी शंकर भागड़ा : उपसभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मैं कह जो रहा हूँ इसको आप किस तरह से इन्टीसिपेट कर रहे हैं? आपको क्या टेलीफ़ोन का स्पेशल नालेज है?

श्री उपसभापति : हाँ, नालेज है, आप सवाल पूछिये।

श्री हरी शंकर भागड़ा : आप किस तरह इन्टीसिपेट कर लेते हैं...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : हाँ कर लेते हैं। कृपया आप जो प्रश्न है...(व्यवधान)

श्री हरी शंकर भागड़ा : आपने मेरा कितना समय खराब कर दिया है।.....(व्यवधान).....

श्री उपसभापति : आपके और साथी खड़े होकर आपका समय खराब कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री हरी शंकर भागड़ा : मैं कह रहा हूँ कि यह समस्या इसलिये पैदा हुई...

श्री उपसभापति : यह समस्या गेहूं इम्पोर्ट करने से सम्बन्धित नहीं है।

श्री हरी शंकर भागड़ा : इस मामले को इतना टेक्नीकल बना दिया है कि अस्तित्व इसका निर्णय एक्सपर्ट ही

कर सकता है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मामला पैदा हो नहीं होता, यहाँ पर प्रोडक्शन कम नहीं है यह आप बार बार कह चुके हैं, गैप-प्रोक्वोरमेंट है जिसके फिल-अप करने के लिये सरकार गेहूँ इम्पोर्ट कर रही है। आप 153 रुपये दे रहे हैं आस्ट्रेलिया के किसानों को सरकार...

श्री उपसभापति : इसमें यह सवाल नहीं उठता...

श्री हरी शंकर भाभड़ा : इतना अगर यहाँ के किसानों को देते तो यह समस्या पैदा हो नहीं होती और जो मैं यह कह रहा हूँ मुझे इस तरह की कोई आपत्ति न होती।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि पहले यह बात बताइये कि इस सम्बन्ध में जो टीम आपके इस सोदे को करने के लिये आस्ट्रेलिया गई थी उस टीम में क्वालिटी कंट्रोल कौन एक्सपर्ट व्यक्ति था और क्या वे गेहूँ की क्वालिटी के बारे में जानकारी रखते थे जिन्होंने यह सौदा वहाँ किया हो?

दूसरी बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में भी आप गेहूँ का बफर स्टॉक बनाते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो इसमें कौन सा कीटनाशक दवाएँ कितनी मात्रा में मिलाकर रखते हैं? इसके लिये क्या आपके क्लब बने हुए हैं?

तीसरी बात यह है कि यह प्रिबेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में जो नियम बने हैं उन नियमों के अन्तर्गत गेहूँ को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी दवाइयाँ आप काम में ला सकते हैं, किस मात्रा तक काम में ला सकते हैं इसके बारे में भी आप जरा बताइये। मान्यवर, इस संबंध में आज आपने जो जवाब दिया है उसमें यह कहा कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन

की रिपोर्ट के मुताबिक आप कह रहे हैं मेरा इसमें आपसे निवेदन है कि देखिये वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन के जो मानदंड हैं उन्होंने मापदंड बनाए हैं वे मापदंड हिन्दुस्तान की परिस्थितियों में भी लागू होते हैं, क्या इसको आपने देखा है। अमूमन पश्चिमी देशों में गेहूँ का प्रयोग घी कर और उसके बाद में बैक्रीज में ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। हाई टेम्प्रेचर में ब्रेड बनती है। इसलिए यदि उसमें कीटनाशी दवाइयों का कोई असर हो तो हाई टेम्प्रेचर में समाप्त हो सकता है। लेकिन आपने यह जो गेहूँ मंगाया है इसमें साफ तौर पर यह बात आपने बताई है कि आप हिन्दुस्तान के दक्षिणी और पश्चिमी कोस्टल एरियाज के अन्दर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की मारफत से इस गेहूँ को आप देना चाहते हैं और हिन्दुस्तान में गेहूँ के बारे में यह प्रथा नहीं है कि इसको घी कर के पिसाया जाए। यहाँ पर गेहूँ को सीधे पिसाते हैं और पीसने के बाद हम चपाती बनाते हैं जो कि बहुत ही लो टेम्प्रेचर में बनती है, हाई टेम्प्रेचर में नहीं बनती। इसलिए कीटनाशी दवाइयों का जो असर अन्य जगहों पर दुनिया में हाई टेम्प्रेचर के कारण समाप्त हो सकता है वह परिस्थिति हिन्दुस्तान में नहीं है। यहाँ का गरीब आदमी चपाती बना कर खाता है, जो बहुत ही लो टेम्प्रेचर में पकाया जाता है। तो वह जो कीटनाशी दवाइयों के तत्व इसमें मिले हुए हैं उनका कितना असर इस परिस्थिति में हिन्दुस्तान के लोगों पर होगा इसके बारे में भी आपने क्या कोई जानकारी प्राप्त की है?

दूसरी बात यह है कि मान्यवर, इस संबंध में आपके एक प्लान्ट प्रोटेक्शन एडवाइजर कृषि भवन में बैठते हैं उन्होंने क्या इस संबंध में कुछ केमिकल एनेलेसिस

[श्री हरी शंकर भाभड़ा]

किया है और यदि किया है तो इस संबंध में उनकी राय क्या है। क्या वे इस बात से इत्तफाक करते हैं कि जो कुछ कीटनाशी दवाइयाँ इस आस्ट्रेलिया के गेहूँ में मिली हुई है वे कायदे के मुताबिक और नुकसानप्रद नहीं हैं। इसके बारे में उनकी क्या ओपीनियन है, यह भी आप बनाने का कष्ट करें।

अन्तिम बात यह है कि मान्यवर, मेरे पास इनफार्मेशन यह है कि इस डोल के अन्दर इस सौदे में कुछ अधिकारियों ने बड़ी धपला किया है। माननीय मंत्री महोदय को भी अन्धेरे में रखा गया है। इस के केमिकल एनेलिसिस की रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय को बताई नहीं गई है और चुपके चुपके यह तथ्य किया गया कि इस गेहूँ का अब क्या किया जाए और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो इस गेहूँ की पड़ोसी देशों में हम एक्सपोर्ट कर दें इस प्रकार की एक योजना चुपके चुपके बनाई जा रही थी। क्या यह बात सही है या नहीं? यह बात सही है यदि आप मान लीजिये इस नतीजे पर पहुँचे, आज तो आप मना करते हैं, मैं जानता हूँ कि आप इस बात को समझते हैं, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप इसकी जांच कराएंगे। जब आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये गेहूँ स्वास्थ्य के लिए नुकसानप्रद हो सकती है तो फिर इस गेहूँ का आप क्या उपयोग करेंगे। यदि आप इसको लाएंगे तो उसमें कितना खर्च लगेगा और इस गेहूँ को धुला कर या फिर किस प्रकार से कहाँ इसका डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे? क्या बेक्रीज में जहाँ पर ब्रेड बनती है, वहाँ पर देंगे या पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन शासन के माध्यम से जन-साधारण को, गरीबों को भी आप पहुँचायेंगे। कृपया इन बातों का जवाब दें। बोलना भी अभी और भी था पर उपसभापति जी बोलने नहीं देते।

राय बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी चैयरमैन साहब, श्री भाभड़ा जी ने तो अपने शक ही जाहिर किये हैं सवाल तो खास नहीं किया... (व्यवधान) सवाल जितने थे उनका जवाब तो मैं तफसील के साथ दे चुका हूँ। जब यह गेहूँ आस्ट्रेलिया से लाया गया तो उस वक्त करीब फोर पार्ट्स इन वन मिलियन से लेकर सेवन पार्ट्स इन वन मिलियन तक दवाइयों का असर था और यह उनकी अपनी गवर्नमेंट के मुताबिक ठीक था और जो यह है वह एक ए० ए० ओ० की प्रोडक्टस वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन का है उसके सेफ्टी माजिन के अन्दर अन्दर है। लेकिन हर एक देश का अपना अलग होता है। हमारा तो ऐसा सख्त नियम है। दूसरे मुल्कों में अगर फोर पार्ट्स इन वन मिलियन यह दवाई हो तो इस्तेमाल हो सकता है, जबकि फोर पार्ट्स इन वन मिलियन तक हो तो भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करते और काडेक्स तो वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन का 10 पार्ट्स इन ए मिलियन इसको एलाऊ करता है लेकिन यह दवा ऐसी है एनाउट्रोथिओन कि यह बीयर आऊट कर जाती है।

हमारे जहाज जिस वक्त वहाँ से चले, दो हफ्ते तीन हफ्ते का अर्सा उनको हिन्दुस्तान पहुँचने में लगता है, इसी अर्से के अन्दर अंदर इसकी यात्रा काफी नीचे आ गई। एक जहाज जगन्नाथ तो 7 जनवरी को चला, उस वक्त वहाँ से एनेलिसिस को गयी तो 7 पार्ट्स इन मिलियन में वह दवा थी, लेकिन जब वहाँ अन लोड किया गया तो यह जो मूरतलिफ फोल्ड जहाज के थे उसमें 0.95 से लेकर 2.85 तक बढ़ाकर इसकी मात्रा हो गयी।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : उपसभापति महोदय, एक बलेरीफिकेशन चाहता हूँ, यह

जो आप एनेलिसिस करते हैं वह सारे में से करते हैं या कोई सैम्पल लेकर करते हैं या केवल एक ही सैम्पल से करते हैं।

राय बोरेंद्र सिंह : जहाँ जहाँ अलग डेर गेहूँ का हो तो उसके हर एक का एनेलिसिस होता है लेबोरेट्रीज के अंदर और हैल्थ डिपार्टमेंट को तसल्ली इस बात में कराई जाती है।

दूसरा जहाज जब यहाँ पहुँचा तो उसमें 0.95 पाट से लेकर एक पाट एक मिलियन तक दवा का असर रह गया। जब वह वहाँ से चला तो साग गेहूँ जो 'स्वीट फ्लव' जहाज में लाया गया उसमें चार पाट से कम मात्रा थी। हमारे यहाँ मैलीषियन हस्तेमाल होता है इस दवा की जगह में और मैलीषियन हम अपने गोदामों में सात या आठ परसेंट तक इस्तेमाल करते हैं, जैसी जबरत समझी जाती है। लेकिन जिस तरह इश्यू किया जाता है गेहूँ उस वक्त तक, हमारा स्टैंडर्ड इतना सख्त है कि करीब-करीब जोर पाट भी नहीं रहना चाहिए उसके अंदर। हमारा स्टैंडर्ड 0.02 का है, बिल्कुल दवा का असर खत्म हो जाना चाहिए और हर गोदाम में इश्यू करने से पहले इस बात की तसल्ली कर ली जाती है। तो फिर इसमें खतरा कोई है नहीं। यह बात बिल्कुल गलत है कि हमारे देश के अफसर पोशीदा तीर पर गये क्योंकि गवर्नमेंट से तो कोई छिपी हुई बात नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, कहीं किस अफसर को भेजा, किस वक्त भेजा। नवम्बर में पहले फूड सेक्रेटरी गये, बहुत सीनियर अफसर हैं, उनके मुतालिक अगर कोई भी किसी को शक हो तो मैं दूर करना चाहता हूँ, जाती तीर पर मैं जानता हूँ, जिम्मेदारी इस बात की ले सकता हूँ। दूसरे हमारे सीनियर अफसर एडीशनल सेक्रेटरी गये

दूसरी बार। एक्सापॉजिटिंग एजेंसी ऑस्ट्रेलिया को वहाँ की गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है तो अगर कोई आने खालत में इस तरह को तस्वीर बनाये कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इतना भारी नये गेहूँ का स्टॉक इसलिए किया था कि हिन्दुस्तान जब खरीदेगा तो जहरीला गेहूँ भेज दिया जायेगा, या जब हिन्दुस्तान ने इसको खरीदा तो उस वक्त जहर मिला दिया गया तो वह इतनी फार पेज्ड चीज है कि जिसके मुताबिक आनरेबल मेम्बर को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

कुछ गेहूँ आ गया है, इस समय 75 हजार टन लोड हो चुका है, वह हमारे गोदामों में आ गया है। अगर यह दवा वहाँ पर इस्तेमाल न होती और बिल्कुल बगैर दवा के भी गेहूँ यहाँ लाया जाता तो हमारे यहाँ लान के बाद भी दवा का इस्तेमाल करता था, उसको बचाने के लिए अपने गोदामों में, और उसका असर भी कुछ देर तक रहता। लेकिन इश्यू से पहले वह खत्म हो जाय इस बात का पूरा इत्मीनान कर लिया जाता है। यह जहरी है कि दवाओं का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि काफी अनाज खराब हो जाता है कीड़ों की बजह से गोदामों के अंदर, यह आनरेबल मेम्बर अच्छी तरह से जानते हैं।

तो सेफ्टी के स्पेसिफिकेशन जो मुख्तलिफ वल्वे आर्गनाइजेशन ने रखे हैं उनके काफी नीचे के स्पेसिफिकेशन में जिस मात्रा में वह दवा वहाँ मिली थी, वह था और यहाँ आने के बाद और कम हो गया इश्यू के पहले बिल्कुल ही नहीं रहेगा इस बात का हम इत्मीनान कर लेंगे और अच्छी तरह से जाँच कर लेंगे।

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, the question is not whether

[Shri Harkishan Singh Surjeet] the Australian Government intentionally tried to mix up something. As the Minister has himself said all Governments have different standards keeping in mind the climatic conditions and the utility of and the wheat they utilise. A news item appeared in the 'Statesman' stated, which the Minister has not tried to convincingly answer, that "Laboratory tests have revealed here that a quantity of the insecticide mixed with the wheat is to the extent of five to eight miligram in a kilogram. The tolerance limit—the extent of which is said to be safe for human consumption in India—is", as the Minister has stated—"0.02 miligram in a kilogram. Officials of the Department of Food are reported to be extremely worried about this." The wheat Board of Australia had said that this is the quantity they have mixed. After that, they have now the contention of the Minister. They say that the effect does not remain by the time they issue it and that this will be brought down to 0.02 miligram in a kilogram. But he himself has stated this here, and that raises some doubts. And it is not a question of arguing but of concern about the food supplied to the people. Earlier also some examples have been made where certain things have been found in the imported wheat and then we had to complain and protest. That is why the Minister also should share the concern of the Members to see that the consumers do not suffer due to the rotten wheat supplied. That is the main point. And that is why we would like the Minister to go into the details because he himself has said, "By the time the wheat is issued for consumption, the residue level will come down further to well within limits prescribed by the rules framed under the Prevention of Adulteration Act." This is the presumption made "by him. That is why I would like to know two things from the Minister. One is, why if such an urgency was not there food was imported, because their intention also comes. You say that by the time we

will have to supply that food to the depots, it will be brought down to the same level as India has estimated on its own initially. And the reports have come. Is there any validity there that tests showed some concern about it? That should be there. Thirdly, I would like to know what is the necessity of importing wheat. On the one hand you are claiming that you are going to stop the import of foodgrains and on the other you are importing foodgrains. So, are you going to stop the import of foodgrains. not due to this reason, so that we are saved of foreign exchange?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter,

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Sir, the issue comes out of imported wheat. We have got large number of varieties in this country. If you pay Rs. 10 more, you can get as much wheat.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can discuss it on some other occasion.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Sir, I am only suggesting that if he ensures some Rs. 20 more to the peasants, we can get any amount of wheat. He need not have to import.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Is he aware of it?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter. Don't reply to that.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: These are the main points that I would like him to answer.

RAO BIRENDRA SINGH: The hon. Member wanted to make a point about wheat prices.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter.

RAO BIRENDRA SINGH: But this is not the subject matter of discussion. **But** I **would** still like to say that the Government cannot depend

upon the assurance given by the hon. Member that if a few more rupees are given, there will be enough wheat available in the country. Government depends more upon its own efforts and has to take the responsibility itself rather than ...

DR. BHAI MAHAVIR: Efforts on imports or production?

RAO BIRENDRA SINGH: For procurement and production, both. Sir, as I have earlier stated, different countries have different standards for use of insecticides for protecting food-grains in storage. In India also we use several chemicals—malathion, methylbrpmide, etc. We have prescribed different standards. But the World Health Organisation and the FAO have not laid down these limits for particular countries. This is by taking into account the conditions in different countries all over the world, and this is a safety margin that they have prescribed. In Australia, as soon as the foodgrains are taken to silos, they are to be protected with some insecticide and naturally we know that this had been treated with some protectant. There is nothing unusual about it. And, immediately as it reached our country, our experts, our analysts have certainly tried to verify as to what was the content of this protectant and certainly it was higher than what we want at the time of issue. But I have already clarified that even in our own godowns it is much higher than what it should be at the time of issue. There is nothing dangerous if it had a higher content at the time it has come and this has saved us the necessity to again use some protectant in the country where we are storing this. This wheat was not purchased for our immediate requirements. This had been made clear several times in this House. This was only to replenish our stocks and the purchases were made at a time when we thought that the prices would be low in Australia. And it was keeping in view all the possibilities of purchases from other countries that wheat was purchased from

Australia and very senior officers were deputed to make that deal. Naturally we cannot make a noise about what we are going to purchase and from where because that always pushes up the prices. That is why some secrecy has also to be maintained.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: May I request the hon. Members that since so many points have been clarified, they may not put the same questions again and again? '

SHRI G. C. BHATTACHARYA (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am putting a question straightaway. Firstly, I want to know whether whatever wheat has been imported, will that be set apart for the consumption of bakeries, so that it will go through the process of high heat and all these things before being consumed, and there will be some chance of its being washed also. Secondly, I want to know whether whatever quantity has not yet been received, will you think of disposing that of in the outside market so that we may not have to live under this doubt whether it is safe to consume it or not. My specific questions are only two.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your questions are very clear. Please do not repeat.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: My questions are only two, namely, whether you will supply all this wheat to the bakeries only, the wheat that has been received; and whether you will think of disposing of in the outside market the quantity of wheat that has not yet been received.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, wheat has been - purchased for our requirements. It is meant for us. But the Government has always the option of using it as it likes. If we want to help some country with this wheat we can do so even if it has come to us. It can be given to somebody as assistance. We always want

urgent public importance

[Rao Birendra Singh] to maintain relations with outside countries and we have been helping needy countries with wheat although we ourselves are not very comfortable in the matter of wheat. We are also exporting rice but this wheat for all practical purposes is now a part of our stocks, whether it is still in Australia or it is on the seas or it has been received. The deal has already been made and it shall be used for &\$. purposes for consumption, for millers also it can be issued. For the public distribution system also it can be used. But I have given an assurance that at the time of issue it is the responsibility of the Government to see that it is safe for consumption in any manner that the consumers want to use it.

श्री शिव चन्द्र शा : उपसमापति जी, मंत्री महोदय स्पष्ट रूप में सदन को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल है ये आपकी तरफ से जो गए आपके इनके नाम हैं : बी० सी० गंगोपाध्याय, बी० एस० राजवन, एस० बी० शारदा और चौथे अफसर हैं नारायण राव, खाद्य विभाग के। तो ये चार अफसर गये हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह साफ-साफ नहीं बता दिया कि इस में इतने-इतने बिबैले पदार्थ हैं? क्या स्पष्ट रूप में बता नहीं दिया? बताने के बाद भी उन लोगों ने सीधेबाजी की है। अखबारों में बात छपी है। मैं इसको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूँ—

“पता चला है कि बेचे हुए गेहूँ को हर एक खेप के बारे में ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को मिलाये गये रसायन की मात्रा के बारे में बता दिया था। हैरानी इस बात की है कि भारतीय अधिकारियों ने फिर भी ज्ञान-बूझकर इस बातका गेहूँ का सौदा किया।”

क्या यह बता दिया गया था कि नहीं इसमें इतनी मात्रा बिबैली है। तब फिर क्यों इसका सौदा किया गया? क्या आपको सूचना बी गई कि इसमें इतनी मिलावट है? यह मेरा पहला सवाल है।

दुनिया के हर एक मुल्क का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। बल्ड हैल्थ प्रायोजनाइजेशन का इन्होंने हवाला दिया। तो पहले यह बतायें कि बल्ड हैल्थ प्रायोजनाइजेशन और ऐग्रीकल्चरल प्रायोजनाइजेशन जो दुनिया के मुल्कों के बारे में, सहनशक्ति के बारे में पता लगाये हैं भारत की जो परिस्थिति है, इसमें भारतीयों की सहनशक्ति कितनी है, उसको कितनी दूर तक वह बर्बाद कर सकते हैं? आपके ऐक्सपर्ट जो हैं, वह कितना बताते हैं। यह मैं इस लिये पूछ रहा हूँ कि इस गेहूँ में प्रत्येक किलोग्राम में पाया गया 5 से 8 मिलिग्राम। ...

श्री उपसमापति : वह जवाब आ चुका है। अखबार मत पढ़िये। अखबार की बात का प्रतिवाद कर दिया, फिर भी आप उसी की पढ़ियेगा? गलत बात मत पढ़िये।

श्री शिव चन्द्र शा : दूसरी बात मैं कह रहा हूँ। मिनिस्टर ने बताया है कि इस रसायन की सहनशक्ति की सीमा भारत में 0.2 मिलिग्राम प्रति किलोग्राम मात्र ही है। लेकिन इसमें पाया गया 5 से 8 मिलिग्राम प्रति किलो।

श्री उपसमापति : कहाँ पाया गया? वह प्रकार ऊपर दिया, फिर आप उसी बात को ले रहे हैं।

श्री शिव चन्द्र शा : बल्ड हैल्थ प्रायोजनाइजेशन ने क्या प्रिक्काइज किया

है और आप क्या प्रिस्काइव करेंगे, यह पूछ रहा हूँ।

श्री उपसभापति : मंत्री जी ने जो नई सूचना दी, उसके ऊपर पूछिए। वह तो पहले ही यह बता चुके हैं। आप बिना बजह टाइम बरबाद करते हैं।

श्री शिव चन्द्र शा : जी हाँ, नई चीज हो पूछ रहा हूँ।... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : वह पढ़कर सुना दिये, फिर सुना देंगे। जो चीज खत्म हो गई उसका बौहराइये मत।

श्री शिव चन्द्र शा : मैं कहता हूँ कि बल्ड हेल्थ ने क्या प्रिस्काइव किया है, यह इन्होंने बताया है?... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : जी हाँ, बता दिया है। कौन आपसे बहस करे।... (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र शा : तीसरा सवाल मरा है...

श्री उपसभापति : आप जैसे बुद्धिमान आदमी जब ऐसे सवाल पूछते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। आप पुछिये, तीसरा सवाल क्या है?

श्री शिव चन्द्र शा : आप जैसे बुद्धिमान जित तर्ह से चलाते हैं, जो भी बोलना चाहे उसको बोलने नहीं देते हैं। आप एक दो मिनट दे बीजिये। रिलेबेंट है, इरिलेबेंट है, आप ही उसकी छटनी करने लगते हैं। आप उसको छोड़ बीजिये कि रिलेबेंट है या इरिलेबेंट है।... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : पूछिये अब आप।

श्री शिव चन्द्र शा : तीसरा सवाल यह है कि आस्ट्रेलिया का गेहूँ मंगाने की जो आपको जरूरत हुई है क्या इसके माने ये नहीं हैं कि फूडग्रेन्स के जो आंकड़े हैं यह उसका दिवाधियापन है?

श्री उपसभापति : फिर मैं रोकूंगा तो आप मानेंगे नहीं। यह सवाल नहीं है।... (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र शा : क्यों नहीं है? (व्यवधान)। क्या येहूँ नुमाइश के लिये मंगाया है, क्या तमाश के लिये वह इंपोर्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट के स्टॉक में नहीं है, इसलिये इंपोर्ट किया जा रहा है और आपका प्रोडक्शन सफिशियेंट नहीं है, इसलिये तो आ रहा है?... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : यह सवाल दूसरा है, शा जी।... (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र शा : कैसे दूसरा है, क्यों इंपोर्ट किया जाता है? चूँकि यहाँ कम है इसीलिए इंपोर्ट किया जाता है?... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया, अब आप बैठिये।... (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र शा : चौथा और आखिरी सवाल है।... (व्यवधान) इस अडल्टेशन ऐक्ट की सीमा से जो वह कहते हैं जहाँ से आयेगा, फिर गोदाम में रहेगा, उसमें घटेगा। गोदाम में पहुँचते-पहुँचते और घटेगा और पेट में जाने से और कम हो जाएगा। ये जो कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है।

[श्री शिव चन्द्र झा]

इस अडल्टेशन एक्ट के मातहत जो लिमिट्स हैं अब तक जो बफर स्टॉक में आपकी रही हैं पहले, कभी ऐसा पाया कि नहीं बावजूद खर्च के ?

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि यह तो बार-बार दोहराया गया है कि किस लिए मंगाना पड़ा। सन् 1981 में डाउट के साल के बाद हमारा बफर स्टॉक 10 मिलियन टन के नीचे चला गया था जिसमें गेहूँ सिर्फ 3 मिलियन टन रह गया था। हम चाहते थे कि उसको रिप्लेनिश करे। आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट बताती या न बताती, यह तो मालूम होता है कि इसके अन्दर दवा इस्तेमाल की गई और एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, मिस्टर नारायण राव उसमें साथ गये थे सिर्फ यह देखने के लिए कि गेहूँ किस किस का है और इसमें कितनी दवा मिलाई गई है। वहां भी टेस्ट करते हैं और यहां आने पर भी मात्रा का टेस्ट करते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है कि आस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बता दिया कि इसमें कितनी दवा की मात्रा है। हमारे अफसरों को भी पूछने का काम है कि इसमें कितनी दवा है और उसके मुताबिक उनका टेस्ट करने का काम था। इसमें शक के लिए क्या गुंजाइश है।

श्री शिव चन्द्र झा : वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने क्या स्टैंडर्ड रखा है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने जितनी मात्रा मानी है वह 10 लाख में 10 हिस्सा है वह मैं बता चुका हूँ।

श्री शिव चन्द्र झा : भारत के सेट-अप में क्या है ?

श्री उपसभापति : वह बता चुके हैं आपने सुना नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : एक मिलियन टन में दस हिस्सा।

श्री कृष्ण चन्द्र पस्त (उत्तर प्रदेश) : साहब यह पूछ रहे थे कि इंडियन कन्डीशन्स में टालरेंस लिमिट इस की क्या है। डब्ल्यू० एच० ओ० का स्टैंडर्ड हो गया। इंडियन कन्डीशन्स में 0.02 मिलियन है क्या ? यह उनका सवाल था।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने पहले अर्ज किया है कि हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड डब्ल्यू० एच० ओ० का दूसरों की निम्नत बहुत सख्त है। फूड एडल्टरेशन एक्ट के मुताबिक 0.02 है यानी मिल के बराबर है और उसी के ऊपर हम चलते हैं।

श्री उपसभापति : मंत्री जी पहले इसका जवाब दे चुके हैं, आप ध्यान नहीं रखते।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : मान्यवर, इस गेहूँ के आयात से देश में काफी चिन्ता है और चिन्ता का कारण है— इस लिए नहीं कि लोगों की बहुत सही जानकारी है, बल्कि लोगों का जो पिछला अनुभव है उससे लोगों को चिन्ता है। आप को मालूम होगा कि कुछ साल पहले अमरीका से गेहूँ आया था सड़ा हुआ था, जहरीला था। जब लोगों ने वह खाया तो मरने लगे और तब हाहाकार देश में मचा और पार्लियामेंट में मचा। इस बैकग्राउंड में फेनाइट्रोथिओन हिन्दुस्तान के स्टैंडर्ड से ज्यादा थी। मंत्री महोदय ने कबूल किया जब गोडाउन्स में यहाँ पर आया तो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा थी। उनको आशा है कि जब तक वह इशू होगा तब तक वह मात्रा कम हो जायेगी। लेकिन इससे देश की

चिन्ता दूर नहीं होगी क्योंकि जब इश्यू होगा तब दूरी होगी या नहीं होगी यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि लोगों का फूड कारपोरेशन के गोडाउन्स का तजुरबा यह है कि वहां से अक्सर ऐसी चीजें निकलती हैं जो खाने लायक नहीं रह जातीं। इस लिए यह चिन्ता है। इस चिन्ता को दूर करने के लिए आपने खुद स्वीकार किया है कि जरूरी नहीं है कि हम इसकी हिन्दुस्तान में ही खपत करें। आप इस को बफर स्टॉक में रखें और किसी ठंडे मुल्क को दे दें जहां इसकी ज्यादा माता खपत में आ सकती है—यहां दीजिए। यहां पर लोग जो रोटी और चपाती के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको आप न दें। एक तो हम यह चाहेंगे क्योंकि यह चिन्ता हो गयी है कि कहीं बिना बताये इश्यू हो जाय और लोगों को बोमारियां हो जायें। इसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिये आप इस बात की गारन्टी दीजिए कि आप इस को रोटी और चपाती बना कर इस्तेमाल करने वाले लोगों को इश्यू नहीं करेंगे। नम्बर दो यह मैं चानना चाहूंगा कि आपने जो यह गेहूं आस्ट्रेलिया से खरीदा है तो यह किस कीमत पर खरीदा है।

श्री उपसभापति : कीमत की बात छोड़िये।

श्री योगेन्द्र शर्मा : कैसे छोड़ूं। मरें श्री और कामा भी न पूछें। हमारे देश में गेहूं की कमी है और बफर स्टॉक बनाने के लिये आप लेते हैं। तो इस का मतलब है कि कमी है और कमी होने का संबंध कीमत से हो जाता है। हमारे माननीय सुरजीत जी ने कहा कि कीमत बढ़ा दी होती तो हमारे देश में ही गेहूं मिल जाता। तो यहां मिल सकता है या नहीं मिल सकता है इस विवाद में मैं इस समय नहीं जाना चाहता, लेकिन कीमत की बात को हम छोड़ना नहीं

1999 RS—6.

चाहते और मैं समझता हूं कि यह कोई गुप्त बात नहीं है और आस्ट्रेलिया से किस कीमत पर आपने इस गेहूं को खरीदा है और हिन्दुस्तान में उस वक्त गेहूं की कीमत क्या थी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य की तत्त्वों इस तरह से करा सकता हूं कि यह गेहूं बिलकुल सफेद हाया खाने के लिये तभी इश्यू किया जायगा और अगर इस के आगे भी वह इतना करना चाहते हैं तो मैं पहले खा कर देख लूंगा और सारे अफसर इस को खा कर देख लेंगे तभी वह इश्यू किया जायेगा किसी को।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप तो मजबूत आदमी हैं, खा कर उसको पचा सकते हैं, लेकिन हम नहीं पचा सकते।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now it is a fair offer from the Minister. You accept it.

राव बीरेन्द्र सिंह : जो अमरीका से गेहूं आया था वह अब इश्यू हो रहा है मुझे मालूम है कि मिला आम तौर पर इस अमरीकी गेहूं की मांग कर रही है क्योंकि उसमें से मैदा अच्छा निकलता है और यह गेहूं अच्छा देख कर खरीदा गया है और आपको भी पसंद आयेगा।

श्री योगेन्द्र शर्मा : बेकरीज को दे दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : किसी न किसी को तो दिया हो जायगा लेकिन अगर आप को खारा है तो आप को नहीं दिया जायगा। मैं यह भी नहीं कहता कि एफ० सी० आई० से जौ अनाज दिया जाता है वह अच्छा नहीं होता...

श्री योगेन्द्र शर्मा : अक्सर।

राव बीरेन्द्र सिंह : अक्सर की बात अलग है। दस लाख टन अनाज एफ० सी० आई० से इश्यू हो रहा है और 298 हजार

[राव वीरेन्द्र सिंह]

दुकानें उसको तकासीम कर रही हैं। तो यह दस लाख टन अनाज जो हर महीने एफ० सी० आई० दे रहा है वह कहाँ जाता है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं आम बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप कहिये कभी कभी, अक्सर नहीं। अक्सर मैं तो जनरल बात आ जाती है। जहाँ ऐसा होता है, शिक्षायात हमारे पास पहुँचती है तो उस की देखभाल की जाती है। लेकिन आम तौर से अच्छा अनाज हो इश्यू किया जाता है।

कीमत के मुताबिक भी मैं अर्ज कर देता हूँ। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। पहले भी हाउस में यह बात आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया से यह गेहूँ खरीदा गया 212.12 डालर्स पर टन के हिसाब से। लेकिन इस में सिर्फ गेहूँ की ही कीमत नहीं है, इस के अंदर फ्रेट भी शामिल है। वहाँ गेहूँ की कीमत अलग नहीं रखी जाती, साथ में शामिल की जाती है। खाली गेहूँ की कीमत हिसाब लगा कर देखा जाय तो उस में और हमारे हिन्दुस्तान में जो कीमत है उन दोनों में ज्यादा लम्बा चौड़ा फर्क आप को नहीं मिलेगा और यहाँ हिन्दुस्तान में आ कर इसमें किराया भाड़ा मिला कर, जब यहाँ पहुँचता है तो 195.57 पैसे इस की कास्ट पड़ी है। उसके बाद हैंडलिंग चार्ज है, लोड किया जाता है, गोदामों में ले जाया जाता है, रेल का किराया है, इस सब से इस की कीमत थोड़ी और बढ़ जाती है।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, though alarming news appeared in the press yesterday, today's press has published a report from the Government side that the Australian wheat is not

contaminated. Sir, in this matter we cannot take any chances. So, I think the Ministry also will be very much concerned about this. As buffer stocks that may be stocked, but thorough research should be made again and also the Government should know whether the wheat could be used for human consumption or not. According to the report of the World Health Organisation, five lakh people fall ill every year and three thousand die every year due to poisoning-by pesticides. Sir, in our country we use nearly 300 grammes per hectare whereas in the West 1,790 grammes are used. Even then in our country, according to the Indian Toxicological Research Centre in Lucknow average Indian could be consume 0.266 milligrammes of DDT with each meal. That means adequate controls are not being enforced for the manufacture of safe pesticides. I would like to request the Minister to make strict enforcement of the Insecticides Act of 1968 because, when a racket was exposed in Haryana in pesticides even then a case was not registered because the police refused to register a case. That was admitted in the State Legislature itself. So, it is high time the Government made strict enforcement of the Insecticides Act of 1968.

RAO BIRENDRA SINGH: I have noted the suggestion of the hon. Member about the use of pesticides and insecticides. But that is with regard to plant protection measures.. This is a different matter. A special type of protectant was used in Australia for the wheat that we had imported and I have clarified the whole position.

श्री सैयद सिद्दीक रज़वी (उत्तर प्रदेश) :

मान्यवर, सदन में एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ इशारा किया गया है। यकीनन इससे हमारी अवाम की जिन्दगी जुड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथियों ने मामले को रखने की कोशिश की है उससे लगता है कि वह आरोप लगाना चाहते हैं और सरकार पर

[श्री सैय्यद सिब्ते रज़ी]

कोई जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। हमारे मंत्री महोदय ने तमाम बातों का जवाब दे दिया है इसलिये मैं सिर्फ दो सवाल ज्ञात करना चाहता हूँ। जैसा इन्होंने कहा है कि हमें पहले से पता था कि किस तरह का इन्सेक्टेसाइड इसके ऊपर लगा हुआ है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह जो माल, गेहूँ हमने खरीदा है वह आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का बफर स्टॉक का गेहूँ है या उनकी ताजा उपज का गेहूँ है? अगर बफर स्टॉक का गेहूँ है तो क्या जरूरत थी कि हम वह इन्सेक्टेसाइड मिला हुआ गेहूँ खरीदें जिससे यकीनी तौर पर नहीं लेकिन शक जरूर पैदा होता है कि यह हमारी अवाम की जिन्दगी के लिये हितकर नहीं हो सकता या नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरे, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा हम इसको पहले बफर स्टॉक में रखेंगे तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितना समय बफर स्टॉक में रखा जाएगा। जिससे यकीनी तौर पर इस बात का पता चल सके कि अब इसमें किसी तरह का कोई शुबह नहीं है। यदि मंत्री महोदय इस समय स्पष्ट करें तो उससे पता चल जाएगा कि कब से गेहूँ कंजम्पशन के लिये दिया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गेहूँ को, जिसके बारे में शक पैदा हो गये हैं, इसे दूसरे गेहूँ के साथ मिक्स करके दिया जाए जिससे इन्सेक्टेसाइडेशन जो गेहूँ में विशैली चीज को रोकने के लिये, कीड़ा को मारने के लिये किया गया है, उसका असर कम हो जाएगा? तीसरी बात मंत्री महोदय के सामने यह रखना चाहूंगा कि क्या आस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने हमारे देश की अथॉरिटी की पहले से इस बात से आगाह कर दिया था कि यह डायरेक्ट कंजम्पशन के योग्य गेहूँ नहीं है। इसलिये बेहतर होगा कि इसे वाश करके, इसका मैदा या आटा

बनाकर उपयोग किया जाए जिससे किसी तरह की गम्भीर स्थिति पैदा न हो जाए?

RAO BIRENDRA SINGH: It is not a question of the Australian Government being warned by India or the Indian Government being warned by Australia. It is our responsibility. We look into all these things and, after all, this news has come in the newspapers after we got it analysed. It was the Health Department which got this tested to see whether it was according to the specifications required, and it is because we took interest and we wanted to ensure that it is safe that it was found that at present, when it landed in India, this was the content. Therefore, it is not a news from outside. After all it is what Government has been looking into, and Government has done this testing. This wheat will be kept in the go-downs till such time as it is required for the public distribution system in any part of the country, but before Issue it will be ensured that it is safe for consumption. If it has to be kept in storage for longer periods in the godowns, we may have to use more protectant ourselves to protect it.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय, ने करीब-करीब कुछ सवालों के जवाब दिये हैं। लेकिन जो खबरें स्टेट्समैन और दूसरे समाचार-पत्रों में छपी हैं वे बहुत ही तथ्यहीनता के खबरें हैं और सारी जनता में एक किस्म का असंतोष पैदा हो गया है और लोग यह सोचने लगे हैं कि बढ़ती हुई आबादी को घटाने के लिए कोई नया तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आप लोगों में यह चर्चा पैदा हो गई है और यह विश्वास पैदा होता जा रहा है कि गवर्नमेंट आबादी को घटाने के लिए कुछ कदम उठा रही है....

(व्यवधान)

श्री सैयद सिद्दीक रशी: भ्रम तो आप फैलायेंगे, जनता में इस तरह का कोई भ्रम नहीं है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : श्रीमन्, मैं दो तीन सवाल करना चाहता हूँ। पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आस्ट्रेलिया से गेहूँ मंगाने के लिए जो टीन वहाँ गई थी उसमें क्या कोई एक्सपर्ट या साइंटिस्ट जांच करने के लिए भेजा गया था?

श्री उपसभापति: इसका जवाब हो चुका है। उन्होंने बताया है कि श्री नारायण राव, जो फूड कारपोरेशन के हैं, वे एक्सपर्ट हैं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : क्या इसका कोई एनेलिसिस हुआ है या एक्सपर्ट की कोई रिपोर्ट है?

श्री उपसभापति : इसका जवाब हो चुका है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मैं नहीं जानता कि इस बारे में कोई एक्सपर्ट की रिपोर्ट है या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर कोई जांच की गई है तो इस गेहूँ में कितनी मात्रा में जहरीली कीटनाशक दवा है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस गेहूँ की जांच आस्ट्रेलिया में हुई है या भारत में अने पर हुई है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस बारे में भारत सरकार की टीम ने कुछ बताया था या आस्ट्रेलिया की सरकार की तरफ से कोई संकेत दिया गया है? अगर इस गेहूँ की कोई जांच हुई है और भारत की टीम की कोई रिपोर्ट है तो क्या आप उसको सदन के सामने पेश करेंगे?

श्री उपसभापति : यह सब उन्होंने बताया दिया है, आपने सुना नहीं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह गेहूँ जो इस समय गोदामों में स्टोर्ड है,

यह कितने समय तक उनमें रहेगा और कब डिस्ट्रिब्यूट होगा? यह तो मानी हुई बात है कि यह गेहूँ आपको या हमको नहीं बांटा जाएगा यह तो आम लोगों को, गरीब लोगों को बांटा जाएगा क्योंकि सड़ा हुआ गेहूँ गरीबों को ही दिया जाता है, आम लोगों को दिया जाता है। पहले भी इसी प्रकार का गेहूँ जो अमेरिका से आता था, आम लोगों में बांटा गया था। ऐसी हालत में मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या बंदवारा करने से पहले या लोगों के पास पहुंचने से पहले, आम लोगों को साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि यह गेहूँ जांच करके दिया जा रहा है और इसमें कोई नुकसानदेह चीज नहीं है और क्या लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा कि यह आस्ट्रेलिया से मंगाया गया गेहूँ है ताकि उनकी मर्जी हो तो वे खरीदें, वरना न खरीदें? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा गेहूँ जो आस्ट्रेलिया से या अमेरिका से या अन्य किसी देश से मंगाया गया था और जो कीटनाशक दवाओं से भरा हुआ था उसकी वजह से हिन्दुस्तान में क्या किसी की मौत हुई है और अगर किसी की मौत हुई है तो उनकी तादाद बताने की कृपा करें।

श्री श्री शंकर भागड़ : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री नारायण राव जो फूड कारपोरेशन के अफसर हैं, वे वहाँ पर किस पद पर हैं? ये किस चीज के एक्सपर्ट हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not important. The same question is being repeated every time, unnecessarily wasting the time.

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Indian people are suffering from so many curable and incurable diseases, and I think a little bit of insecticides will cure them.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has replied to that.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: It is a very relevant question, sir.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Let him answer my question first.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: He *pan* answer both. The Agriculture Ministry has in the past, done a lot of research about the insecticides like the DDT and all that. Has any tolerance or resistance been developed to this type of drug because in the case of malaria...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has replied that tolerance has been developed.

राव बोरेंद्र सिंह: डिप्टी चैयरमैन साहब, पहले मैंने जो जवाब दिया था, उस वक्त मैंने सिर्फ यह समझा था कि यह रिपोर्टिंग मिस्वीवियस है, लेकिन माननीय सदस्य को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पोलिटिकल हाथ भी है। इस तरह की शरारत इस खबर के अन्दर थी और इसको यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, दाद देता हूँ मैं आपके इमेजिनेशन की, तख्त्याल का कि आबादी को कम करने के लिए यह वहीट मंगाया गया है... (व्यवधान)...

1977 के इलेक्शन से पहले यह भी बताया गया कि टोके लगाये जा रहे हैं बच्चों पर और यह इसलिये लगाये जा रहे हैं... (व्यवधान)... आप तो यहाँ तक भी कह सकते हैं कि जो नहीं बनाई जा रही है, अगर उसमें कोई हाइड्रल प्रोजेक्ट है, तो बिजली पहले निकाल लो जाती है और किसानों को पानी बगैर बिजली के दिया जाता है। मैं आपके तसब्बुर को दाद देता हूँ। बहुत हद तक ऊपर तक सोचते हैं।

मैं अजें कर रहा था कि मैं पहले बता चुका हूँ कि...

श्री उपसभापति: उसको दोहराइये नहीं।

राव बोरेंद्र सिंह: ...बीज टेस्ट किया जाता है और जहाज पर लादते वक्त कितनी मात्रा थी, यह मैं दोनों जहाजों के आंकड़े बता चुका हूँ। यहाँ पहुँचे तब क्या मात्रा इस दवा की थी, यह भी मैं बता चुका हूँ और इश्यू करने के पहले जो फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के तहत जो प्रिस्क्रीप्शन लिमिट है, अगर उसके अन्दर होगा तो वह इसको पास कर देंगे और तब इश्यू होता है। ऐसे इश्यू नहीं होता है, फूड कारपोरेशन के गोदामों से। तो मेहरबानी करके आप ऐसा गेहूँ न खाइये और अपने राशन कार्ड वापस कर दीजिये। लेकिन दूसरे लोगों को... (व्यवधान)... परेशान मत करिये... (व्यवधान)

श्री जी० सो० मट्टाचार्य: डिप्टी चैयरमैन साहब, आप कुछ तो कन्ट्रोल कीजिये यह क्या जवाब है कि राशन कार्ड वापस कर दीजिये, टेलीफोन खराब है तो... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: दूसरों को बोलने दीजिये... (व्यवधान)...

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी: मेरे तीसरे सवाल का जवाब... (व्यवधान)...

श्री जी० सो० मट्टाचार्य: ... यह क्या है कि वापस कर दीजिये... (व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी: मैंने पूछा था कि क्या इस गेहूँ को विदेशों में इम्पोर्ट करने के बाद देश में लोगों को मीठे हुई थीं, इसके बारे में मैंने सवाल पूछा है? (व्यवधान)...

राव बोरेंद्र सिंह: इसके आने से कोई मीठे देश में नहीं हुई और न होगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't repeat the questions and the replies.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Not at all. You will see that I am not repeating. But the last statement which the Minister made—whether out of pique or anything, I do not know—of returning the ration cards by certain Members...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: The cure is worse than the disease, that way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no disease.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: As you said, Mr. Deputy Chairman, we cannot go into the question whether such wheat purchases are best evidence of our efforts at acquiring self-sufficiency or whether purchasing wheat at a higher price from abroad was right or not. I have two specific questions to ask. I remember an earlier occasion, perhaps about two decades back when our country was not self-sufficient—at present it is—when a shipment from the USA came and ultimately it came out that that shipment consisted of a consignment of wheat which had been declared in the USA as unfit for human consumption. Under PL 480 that wheat was shipped to India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different question.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Not a different question. I would show you the correlation. It is related to that. It was an open scandal a long time back. This is how the U.S.A. utilised their surplus stock of wheat which was declared unfit for human consumption. In this report, there is a particular line which raises the suspicion that perhaps the Australian authorities considered this stock of wheat to be unfit for human consumption there. I quote:

"They had clearly told officials to examine whether the insecticides

urgent public importance

mixed would be fit for human consumption in India."

They perhaps implied that it was not considered fit for human consumption in Australia. Is it so? Is there any reason to suppose so? Was this wheat contracted to be purchased by the representatives of our Government even after knowing that?

Secondly, from the replies so far given by the Minister, it seems that he discounts whatever allegations have been made in this report, thereby suggesting that unnecessary scare has been spread by this news item. The newspaper has obviously published it with full responsibility. If they have done it in an irresponsible manner, as the Minister seems to suggest, what remedial measures would he suggest?

RAO BIRENDRA SINGH: It is not for me to suggest what action can be taken against the journalists who have misreported things or twisted them. It is a matter for the Press Council to take notice of. We shall see how we can rectify these things. The hon. Member has rightly suggested that things of this kind create scare. After all, Australia—if I know correctly—is exporting 10 to 12 million tonnes of wheat every year to all the parts of the world and it is the same kind of insecticides they used and it is the same kind of wheat that is consumed all over the world. But, as I have stated earlier, the Indian standards are very strict. I have already given replies to his other questions. I do not think there is any need to worry about it.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Was it unfit for human consumption there?

श्री बानु प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) :
श्रीमान्, मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
पहला तो यह है कि जो इनसेक्टिसाइड
इस्तेमाल किया गया, इसका टेक्नीकल वेस
क्या है ? कौन सा कैमिकल है जो इसमें

मुख्य रूप से लगा है। दूसरा सवाल यह है कि यह इन्सेक्टसाइड अपने देश में इस्तेमाल होता है या नहीं और यदि नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? हम लोगों ने क्या दूसरे इन्सेक्टसाइड प्रयोग करना बेहतर समझा। तीसरी बात यह है कि मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि किस एजेंसी के द्वारा इसकी जांच कराई गई, एनेलेसेज कराई गई। क्या वह फूड डिपार्टमेंट की एजेंसी है अथवा कोई ऐसी एजेंसी जिस पर लोगों को भरोसा हो सके। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि चाहे जितना कृषि मंत्री जी सफाई दें, मैं उनकी सफाई में अविश्वास भी नहीं करता परन्तु यह बात जब देश में फैल चुकी है तो और अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया है उस वातावरण को दूर करने के लिए मेरा सुझाव तो यह है कि इसको आप इंडियन टोक्सिकोलोजिकल रिसर्च सेंटर, लखनऊ में भेजें और वहां से रिपोर्ट लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पुरानी मान्यताएं थीं इन्सेक्टसाइड के बारे में उनमें बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं। जो पहले सेफ समझी जाती थीं वे अब अनोफ समझी जाती हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इससे फौरन मौज हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। ये इन्सेक्टसाइड कभी शरीर के अंदर धीरे धीरे एकत्र होते रहते हैं और जब तक एक सर्टन लेवल तक नहीं पहुंचते हैं तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिये इनके प्रयोग में अधिकतम सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लोगों का विश्वास तभी जागेगा जब एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बाडी द्वारा इसकी जांच कराई जाये। अगर केवल फूड डिपार्टमेंट के लोग करते रहेंगे तो मुझे डर है कि जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। तो मैंने उनसे पूछा है पहला तो केमिकल बेस क्या है यह बतायें... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : सब बतायेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : केमिकल बेस के मुताल्लिक मैं नहीं जानता डिप्टी चेयरमैन साहब कि क्या इसका केमिकल बेस है... यह दवा जब हमारे यहां इस्तेमाल नहीं हो रही है। मैंने बताया कि चार पांच और केमिकल्स हैं जो हमारे देश में इस्तेमाल किये जाते हैं। अगर आप इंटरस्टेड हैं तो मैं उनका नाम दे देता हूँ... (व्यवधान)

श्री मानु प्रताप सिंह : इसका केमिकल बेस क्या है, क्या इसमें डी डी टी तो नहीं है। अगर डी डी टी लेश मात्रा में भी है तो वह मनुष्य जाति के लिए घातक है। या आप इतना ही कह दें कि क्या है, यह न बतायें इतना ही केवल बतायें कि डी डी टी इस्तेमाल नहीं होती है... (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं यह भी नहीं कह सकता हूँ जब कि मुझे मालूम नहीं है, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। आप ऐसी बात पूछें, अगले साल क्या करेंगे, कैसे तैयार की जाती है, क्या इसका ट्रायल आस्ट्रेलिया में हुआ, क्या हुआ तो... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : जब पता नहीं है क्या इन्सेक्टसाइड है तो जांच क्या हुई... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप सन्न रखिये, अभी उन्होंने जवाब समाप्त नहीं किया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरी मिनिस्ट्री को मालूम है, उनका कहना है कि यह आर्गेनोफास्फेट कम्पाउंड है एक किस्म का जो मैलेशियान से मिलता जुलता है, मैलेशियान से जो हम इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। आप शायद ज्यादा जानते हों दवाइयों के बारे में...

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : डी डी टी है या नहीं वे यह पूछ रहे हैं... (व्यवधान)

राव बोरेन्द्र सिंह: डो डो टी नहीं हुई
फिर... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: वे लखनऊ से जांच
कराने के लिए कह रहे हैं... (व्यवधान)

राव बोरेन्द्र सिंह: जो मंलोयिमान...
(व्यवधान) यह आर्गेनिक मंटीरियल है
कोई। तो बाकी ज्यादातर सुझाव ही है
माननीय भानु प्रताप जी के, कि दूसरी
सेबोरेडोज से जांच कराई जाय। जैसे
हमारे प्रोबेशन आफ फूड एडल्टेशन एक्ट के
अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री की भारी जिम्मेदारी
बनती है और वे ही इसको टेस्ट कराते हैं,
उनकी अपनी सेबोरेडोज भी है, लेकिन
एहतिपातन उनका सुझाव मानने में मुझे
कोई एतराज नहीं है, इसको और भी दिखा
देंगे।

REFERENCE TO THE REPORTED HARASSMENT OF SCHEDULED CASTES FAMILIES IN NORTH ARCOT IN TAMIL NADU

श्री बुद्ध भिन्न मोर्च (भांग्र प्रदेश):
माननीय उपसभापति जी, तमिलनाडु के
कोटाजम गांव में जो जिला मार्च आरकाट
में आगे पड़ता है, वहाँ करीब 13 शोषित
समाज के परिवार, जिन्हें लोकायुक्त के परिवार
खाताबदोश बना दिये गये हैं। इनके गांव
में समस्याएं हैं। पुरानी जमीन को तो
जमींदारों ने दबा लिया, जहाँ पर वे अपने
मुखे दफनाने थे, नयी जगह पर कहीं दफनाने
नहीं दिया जा रहा है, पीने के पानी की
कोई व्यवस्था नहीं है, जाना बरका कुआँ नहीं
है और जो सब्जियों का कुआँ है उस पर उन्हें
खाने नहीं दिया जाता है। भय तथा अशुल्का
का अतावरण फैला हुआ है और पास के गांव
में भी जहाँ ये 13 शोषित समाज के परिवार
गांव छोड़कर भले गये हैं वहाँ पर यह
अतावरण फैलता जा रहा है।

श्रीमन्, यह बारदात शुरू हो जाती है
पिछले सितम्बर से जबकि एक शोषित समाज
की बुढ़िया मर गयी थी और उसको दफनाने
गये तो जमींदारों ने उसे दफनाने नहीं दिया,
उसके बाद में 15 जनवरी को एक बारदात
हुई, दो मार्च को टाईम्स आफ इंडिया में छपा
और तीन मार्च को आपने मूझे यहाँ पर इसको
रखने की इजाजत दे दी है, मैं इसमें और
ज्यादा बात न कहकर टाईम्स आफ इंडिया
का कोटेशन देकर अपनी बात को समाप्त
करता हूँ।

I quote:

"The cold war turned hot 01
January 15 when the Scheduled
Castes refused to beat drums at the
funeral of the father of the village
headman, Kappu Reddiar.. The
next day, Murugesan, a Scheduled Caste,
charged that Mallika, hi* 23 year old
wife, had been abducted and raped by
four caste Hindus.. Mallika, contacted at
Mulvai village asserted that she was
forcibly I away by four persons and
criminally assaulted. She, however,
pleaded inability to give details as she
lost consciousness."

•\era!
tary of the 'Adi Dravidai
Security Movf' ?ged ths'
had refused to registe-
oral complaint made on Jan;
caste Hindus and
id that the c •\oultS
have -led and S.C. brought
^ village but for the 5
social service 'Foreign Connec-
tions*."

श्रीमन्, मीनाक्षीपुरम की बारदात
भी ऐसी ही थी और बाद में वहाँ पर
वर्तन हुआ। इसके साथ ही साथ
तिलानवेली की भी ऐसी बारदात थी
कि जमींदारों ने शोषित समाज के खेत
मजदूरों को बहुत तंग किया। पुलिस
आधिकारियों ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने